मूल्य : ₹ 25/-

ISSN-2231-1602

आपका तिस्ता-हिमालय

हिन्दी मासिक

वर्ष : 10, अंक : 108, अक्टूबर-2019

राष्ट्र के लिए घातक है 'हिंदूराष्ट्र' की अवधारणा

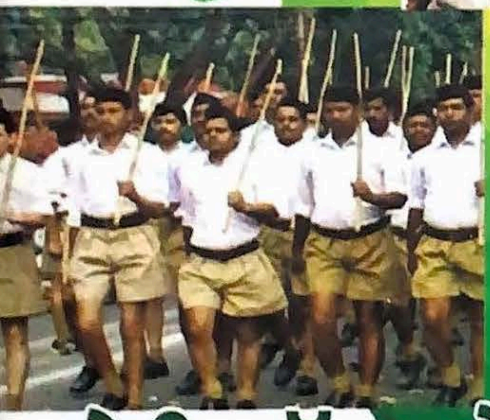

मोदी कॉमनसेंस और भीड़ संस्कृति

संपादकीय: राष्ट्र के लिए घातक है 'हिंदूराष्ट्र' की अवधारणा....................05

वर्तमान आर्थिक संकट के पीछे पूंजीवादी व्यवस्था मूल रूप से जिम्मेदार....07

युद्धोन्माद,कारपोरेट और वैश्विक अर्थव्यवस्था..........................08

वन नेशन नो इलेक्शन..10

गांधी बनाम गांधी..11

अमर शहीद भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार..............................12

मोदी कॉमनसेंस और भीड़ संस्कृति..13

अरे, ओ भैंस का दूध पीनेवालो!...14

रोचक उपन्यास 'धेनुमती के तीरे'...15

बुरा मत मानो...16

जीवन प्रवाह के सजीव बिंब...17

जय चक्रवर्ती के तीन नवगीत..19

पचास साल बाद..20

कहानी: संयोग...23

देश बिकने नहीं दूंगा...25

धारावाहिक उपन्यास: जीवन-यात्रा..27

धरती पर जीवन...28

अक्टूबर-2019
मासिक
मूल्य: 25/-(पच्चीस रुपये)

स्वामी/प्रकाशक एवं मुद्रक रंजू सिंह द्वारा मुक्तधारा प्रेस एंड पब्लिकेशन्स के लिए मुक्तधारा प्रेस , अपर रोड, गुरुंगनगर, पो. प्रधाननगर, सिलीगुड़ी-3, जिला दार्जिलिंग (प.बं.) से मुद्रित एवं 'अमरावती' अपर रोड गुरुंगनगर, पो. प्रधाननगर, जिला- दार्जिलिंग (प.बं.) से प्रकाशित, संपादक: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह
मो: 094340-48163
email : mag.himalayprahari@gmail.com
muktadhara2006@rediffmail.com
Website : www.teestahimalaya.org
RNI No. WBHIN/2010/34186

विज्ञापन विभाग:
ओझा मेंशन, प्रथम तल, हिलकार्ट रोड, सिलीगुड़ी-1, जिला: दार्जिलिंग, प.बं.
ब्यूरो चीफ : डॉ. डी.आर. नकीपुरिया, 5/6 आईनगस भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-1

प्रबंधन: प्रदीप केडिया, सिलीगुड़ी

कानूनी सलाहकार: ओम प्रकाश शर्मा, सिलीगुड़ी / सुदीप कुमार, कोलकाता / राज राजेश्वर सिन्हा, 57-स्कूल रोड, पूर्व पुटीआरी, ग्राउण्ड फ्लोर, कोलकाता-700093

लेखा-निरीक्षक: राज कुमार बिहानी

संपादकीय प्रभारी: शैलेन्द्र चौहान, 34/242, सेक्टर-3, प्रतापनगर, जयपुर-302033, राजस्थान

क्षेत्रीय प्रतिनिधि: शेख मोहम्मद बनिहाल, डोडा, जम्मू-कश्मीर
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ. सत्यभामा आड़िल, शंकर नगर, छत्तिसगढ़, रायपुर.।
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ. मूलचंद गौतम, शक्तिनगर, चंदौसी, मुरादाबाद-202412, उत्तर प्रदेश।
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: प्रो. मोहन सपरा, इ.जी.-1083, गोबिन्दगढ़, एसडी कॉलेज रोड, जालंधर, पंजाब।
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: सुरेश सेन निशांत, गांव सलाह, डॉ. सुन्दर नगर-1, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश-174401.
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: गौतम सिन्हा, सिक्किम
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: आलोक शर्मा 'प्रवीण', सिलीगुड़ी
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ.देवेन्द्र प्रसाद सिंह, सासाराम-821115, बिहार
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ. चेतना राजपूत, डी-II, 44/3, अर्मामेंट कॉलोनी, गणेशखिंड, पुणे-411007
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी, 83-ए काशिपुर रोड, ओम रेसिडेंसि, बी.एल.-3, फ्लाट-3ए, कोलकाता-700002
क्षेत्रीय प्रतिनिधि: विक्रम सिंह, उत्तराखंड, मो: 090122-75039
स्वास्थ्य संपादक: डॉ. रंजु नकीपुरिया, नई दिल्ली 7838011230

डिजाईन: कमल प्रसाद दहाल

- पत्रिका से संबंधित सभी तरह के विवाद सिलीगुड़ी न्यायालय द्वारा ही निपटाये जायेंगे।
- रचनाओं में व्यक्त किये गये विचारों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्र के लिए घातक है 'हिंदूराष्ट्र' की अवधारणा

(15 मार्च 2002 में प्रकाशित 'आपका तिस्ता-हिमालय' के संपदकीय को कुछ ख़ास कारणों से पुन: प्रकाशित किया जा रहा है। -संपादक)

अवाम के लिए यह सबसे कठिन काल है। राष्ट्र की एकता-अखंडता विपन्न है। शत्रु देश के भीतर भी है और बाहर भी। हम विकासशील राष्ट्र हैं। हमारे पास अपार जनबल है। श्रम की शक्ति है। विदेशी दुश्मनों से लड़ने के लिए एटम की ताक़त है। बड़ी मात्रा में तोप-गोले व बम-बारूद हैं। अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र हैं। तथा राष्ट्र के नाम पर मर-मिटने वाले जाँबाज सिपाही हैं। देश में भामाशाहों की कमी नहीं है। अवाम की आंखों में दुश्मन से जंग जीतने का सपना है और सपने को हक़ीक़त में बदलने का साहस भी...।

हमने माना कि हमारे पास वह सब कुछ है, जिससे हम देश के दुश्मनों से लड़ सकते हैं। हालांकि किसी भी जंग में हार और जीत संसाधनों और काफ़ी हद तक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मगर हमारी चिंता तो इस बात को लेकर है कि देश के भीतर जो देश के असली दुश्मन हैं आज वे ही खुद सबसे बड़े राष्ट्रभक्त होने का दम्भ भर रहे और वक़्त बेवक़्त अपनी राष्ट्रभक्ति का दावा पेश कर रहे व खुद को देश और संविधान से ऊपर समझ रहे। सिर्फ़ इतना ही नहीं वे देश के संविधान और इतिहास को मूलत: बदलने को ले सर्वाधिक तत्पर दिख रहे। वे चाहते हैं कि यह देश विशुद्ध हिंदू राष्ट्र बने और उनके हिसाब से इसका इतिहास,भूगोल व संविधान लिखा जाये। सिर्फ़ इतना ही नहीं,बल्कि शिक्षा की बुनियाद को भी विज्ञान आधारित नहीं, विश्वास आधारित बनाना चाहते हैं और अपनी आस्था की बुनियाद पर राष्ट्रभक्ति का पैमाना सुनिश्चित करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इनके मुताबिक अवाम का जो तबका इनके मजहबी जुनून में शामिल नहीं है वह राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। उसे पाकिस्तान अथवा और कहीं चला जाना चाहिए। भारत की एकता-अखंडता नहीं, बल्कि इन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारतीयता नहीं,बल्कि इन्हें सिर्फ़ हिंदुस्तान चाहिए। एक ऐसा हिंदुस्तान जहां सिर्फ़ एक नस्ल के लोग रहते हों और एक भाषा बोली जाती हो। आधुनिक व विकसित भारत नहीं, बल्कि दुनिया के सामने झोली फैलाता बदहाल फटेहाल हिंदू राष्ट्र!

देश के भीतर जो देश के दुश्मन हैं वे संगठित हैं। सक्रिय हैं। सर्वाधिक मुखर हैं। राष्ट्र की एकता-अखंडता के खिलाफ़ वे तनकर खड़े हैं। धर्म, संप्रदाय व नस्ल के नाम पर वह देश को बांटना चाहते हैं। तोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र एक ही रंग में रंग जाये। आदमी की पहचान इंसानियत से नहीं, बल्कि रंगों से हो। मानवीय गुणों की वजह से नहीं बल्कि आदमी धर्म व संप्रदाय से जाना जाये। ऐसी सोच निस्संदेह फासीवादी नजरिये का द्योतक है जो हमारी संपन्न विरासत व अतीत के श्रम-संघर्षों से अर्जित जनवादी मूल्यों को सिर्फ़ ख़ारिज ही नहीं करती, उस पर निरंतर बर्बर हमले कर रही है। नस्लीय संकीर्णता के बढ़ते इस ख़तरे से, अप्राकृतिक हिंसक हमले से आप बताएं हम कैसे लड़ेंगे..? क्या, एटम की ताक़त और हमारे जाँबाज सिपाही देश को टूटने से बचा सकते हैं? नहीं। देश की जनता को, प्रबुद्ध लोगों को इसके लिए आगे आना होगा। और इसके लिए यह जरूरी है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के मंसूबे को समझें और इसके भावी भयानक ख़तरे से अवाम को सावधान करें। दरअसल विविधता के भीतर जो एकता है वही इस राष्ट्र की असली ताक़त है और पहचान भी। सांप्रदायिक घृणा का विस्तार हमारी सांस्कृतिक विरासत को कमजोर बना रहा है। अखंड भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं इससे कमजोर पड़ रही हैं। देश के भीतर देश के दुश्मनों की यह जो चाल है एटम के विनाशकारी हमले से भी अधिक भयंकर है। घातक है। रंगों पर हमले! प्रतीकों पर हमले!! मां के गर्भ में पल रहे देश के भविष्य पर हमले!!!... अगर देश को टूटने व तबाही के मंजर से बचाना है तो हमें इस बर्बर हमले के खिलाफ़ संगठित होना होगा, मुखर होना होगा। यह वक़्त की एक बड़ी चुनौती है। हर हाल में हमें इसका सामना करना होगा।

देश के संविधान तथा राष्ट्रसत्ता को भी अपनी भूमिका साफ करनी होगी। हमारा संविधान तो अपनी निजता में अपनी जगह क़ायम है लेकिन इस हक़ीक़त से हम क़तई इंकार नहीं कर सकते कि राष्ट्रसत्ता निरंतर देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान की निजता तथा संघीय ढांचे की बची-खुची गरिमा व ताक़त को शातिराना तरीक़े से ध्वस्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। संभव है कि निकट भविष्य में हमारी अदालतें नस्लीय सत्ता की कठपुतली बन कर रह जायं।

हम नहीं चाहते कि राष्ट्र की संप्रभुता खंडित हो तथा यह टुकड़ों में बंट जाय और इस पर फासिस्ट शक्तियों का निरंकुश राज हो। दरअसल हम देश को तबाही के दौर से गुजरने देना नहीं चाहते हैं,इसलिए वक़्त रहते बुनियादी सवालों को हम उठा रहे। तालिबान की तर्ज पर 'नये हिंदुस्तान' की अवधारणा की हम पुरजोर मुख़ालिफ़त करते हैं। मानवीय मूल्यों पर हो रहे निरंकुश हमले की हम निंदा करते हैं। शिक्षा-संस्कृति की बुनियाद को नेस्तनाबूद करने की संगीन साजिश का खुलासा राष्ट्रहित में बेहद जरूरी है।

इस दुनिया में मुसोलिनी व हिटलर अब नहीं रहे। मगर मानव-रक्त-पिपासु उनके असंख्य कुनबे अब भी इस धरती पर मौजूद हैं। उनकी दरिंदगी के क़िस्से लोग अभी तक भुले नहीं हैं। आप जानते हैं, बेरहम हिटलर ने पुरी दुनिया को एक ही रंग में रंगना चाहा था। इसके लिए उसने नस्लीय श्रेष्ठता पर ख़ास जोर दिया। उग्र राष्ट्रवाद का वह एक बड़ा प्रवर्तक था। उसकी राष्ट्रभक्ति को संभवतः जनता ने समझने में चूक की जिसका ख़मियाज़ा सिर्फ़ जर्मनी का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को, सभ्यता को, मानव-संस्कृति को भुगतना पड़ा। ज़ाहिर है दुनिया उसे अब भी भुगत रही...। जो लोग हिटलर के खिलाफ़ खड़े हुए अथवा जिन्होंने उसके रंग में रंगने से इंकार किया, वे हिटलर की बर्बरता की भेंट चढ़ गये। असंख्य निर्दोष लोगों की हत्याएं उसकी दरिंदगी को बखूबी दर्शाती हैं। यहूदी युवतियों की जांघों तथा उरोजों पर लोहे की गर्म सलाखों से

दागे गये निशान- 'हिटलर सैनिक दस्तों की वेश्याएं' -आज भी मानवता को बेआबरू तथा विश्व इतिहास को कलंकित कर रहे हैं...। हालांकि हिटलर ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया, उस पर उसे गर्व था। चूंकि वह खुद को जर्मनी की श्रेष्ठ संतान समझता था, इसलिए वह पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता था। वह अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था और इसकी शुरुआत उसने पहले अपने ही देश से की। ***फासीवादी दर्शन इंसान व इंसानियत के खिलाफ़ जाता है। वह सर्वप्रथम परंपरा के सकारत्मक मूल्यों को धूलिसात् करता है। वह इतिहास व विज्ञान को अपने विश्वासों के अनुकूल गढ़ता है। उसे विकृत बनाता है।*** वह शिक्षाा को विज्ञान की मज़बूत बुनियाद पर खड़ा नहीं करता बल्कि धर्म की कमजोर बुनियाद पर, अंध-आवेग पर उसे टिकाये रखना चाहता है। और इसके लिए नये-नये मुहावरे गढ़ता है। हिटलर ने भी यही किया। फ़िर भी वह जर्मनी को नहीं बचा सका।

पिछले दिनों हमने 'हिटलर के गेस्टापों' की दरिंदगी गुजरात में देखी...। हिटलर की जालिम करतूतों पर गर्व करने वालों तथा उसे अपना आदर्श मानने वालों की पहचान आज ज़रूरी है। पूरी दुनिया को ही धधकती आग में झोंकने वाला बेरहम हिटलर पुनः जीवित हो उठा है। पिछले दिनों आपने भी नरेन्द्र मोदी के गुजरात में देखा कि किस तरह एक गर्भवती महिला के पेट को तलवार से चीर कर कथित रामभक्तों ने अपनी बर्बरता का पिरचय दिया! शैतानों ने जीवित युवती की भ्रूण से बच्चे को निकाला और धधकती हुई आग में झोंक दिया! दरअसल वह इंसानियत का नृशंस क़त्ल था न कि किसी मुस्लिम का! रंगों व प्रतीकों के आधार पर उन्होंने असंख्य असहाय-निर्दोष लोगों की निर्ममतापूर्वक हत्याएं कीं। पेट्रोल डालकर घरों-मकानों व दुकानों में आग लगायी। लूट-पाट की। अनगिनत महिलाओं से बलात्कार किये। हिटलर की पशुता व बर्बरता से संपूर्ण गुजरात त्राहिमाम्-त्राहिमाम् करता रहा और गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाही पर हिटलर की तरह गर्व करता रहा...।

मोदी की गौरव यात्रा, तदुपरांत विजय यात्रा...! यह किस बात के लिए? जिसकी की जगह जेल में होनी चाहिए वह गुजरात में गौरव यात्रा निकालता है और अफ़सोस कि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा दूसरा अपराधी उसे संरक्षण देता है। तब देश का संविधान सचमुच कितना-असहाय व बौना नज़र आता है...! जब देश में ऐसे हालात उत्पन्न हों तो हम सोचने पर विवश हो जाते हैं। हर हाल में इस देश को टूटने से बचाना होगा। जम्हूरियतपसंद अवाम को अपनी धर्मनिरपेक्ष भूमिका तय करनी होगी। ***इंसान से बड़ा कोई धर्म अथवा मजहब नहीं हो सकता। इंसान और इंसानियत के खिलाफ़ जो खड़ा है वह देश के संविधान व राष्ट्र का सबसे बड़ा शत्रु है।***

आज देश में अनेक समस्याएं हैं- महंगाई, भुखमरी व बेरोजगारी तो हैं ही। साथ ही युवकों की मानसिक विक्षिप्तता और किसानों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृति। जीवन के सभी क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दखलंदाजी, विदेशी प्रचार माध्यमों के बढ़ते हस्तक्षेप, देश तोड़ने की साम्राज्यवादी साजिश, आतंकवाद, अलगाववाद, नस्लीय विभेद, धार्मिक उन्माद, मानव-मूल्यों पर बढ़ता-गहराता संकट, टूटता-बिखरता घर-परिवार और अमरीकी साम्राज्यवाद के समक्ष घुटने टेकती हमारी केंद्रीय राजग सरकार! एक साथ इतनी समस्याएं और उससे जूझता हुआ आम आदमी किस ओर जाय? धार्मिक उन्माद व सांप्रदायिक फसाद इन समस्याओं का कतई समाधान नहीं हो सकता। हालांकि बर्बर सत्ता व फासिस्ट ताक़तों के लिए ये संजीवनी ज़रूर हैं। ज्ञान-विज्ञान व इतिहास की रोशनी में हमें सच्चाई को समझना होगा। वैचारिक तौर पर एक संगठित राष्ट्र ही देश के दुश्मनों से लड़ सकता है।

'हिंदूराष्ट्र' की अवधारणा राष्ट्र की एकता के लिए घातक है। यह फासिस्ट शक्तियों की सोची-समझी साजिश है। आप प्रतिवेशी राष्ट्र पाकिस्तान को देख कर बखूबी यह समझ सकते हैं, वह गरीबी-भुखमरी से अपने लोगों को निजात नहीं दिला सकता मगर आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रयोजक है। क्या हम भी वहीं पहुंचना चाहते हैं, आज जहां पाकिस्तान खड़ा है! बेशक हमारा जवाब होगा नहीं। ***आज देश का शासक जो चाहता है ज़ाहिर है भारत की जनता वह नहीं चाहती है। आतंकवाद जम्हूरियत का सबसे बड़ा शत्रु है। आज जम्हूरियत को दफ़नाकर खुद अपनी ही कब्र खेदने में लगा हुआ है पाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी राष्ट्र अमरीका सिर्फ़ दक्षिण एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। आज पाकिस्तान बुरी तरह उसके शिकंजे में है। लेकिन देश के राजनैतिक हालात साफ़तौर पर संकेत दे रहे हैं कि कल मोदी का हिन्दुस्तान अमेरिका के गिरफ्त में होगा।*** फिलहाल भारत-पाकिस्तान की बंदर बांट की लड़ाई में वह सब कुछ हड़पने को ले तत्पर है। ग़ौरतलब है सोवियत संघ अपने विघटन के बाद अब वह हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं रहा। चीन खुद को संभालने और आर्थिक तौर पर मज़बूत बनाने में व्यस्त है। दूसरी ओर सीमा पर आतंकवाद से जूझता विकट परिस्थितियों के सम्मुखीन है भारत। देशभक्त, प्रगतिशील जनवादी शक्तियों की एकजुटता ही फासिज्म व साम्राज्यवाद के आक्रमण से हमें बचा सकती है। हम परंपरा के सकारात्मक मूल्यों की बुनियाद पर ही अपना रास्ता तय करेंगे। बहुविध भाषाओं व संस्कृतियों का यह विशाल देश अटल-आडवाणी तथा मोदी के मुताबिक नहीं चल सकता। हमें भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। हिंदू-मुसलमान, सिख-ईसाई एवं जो अन्य अकलियतें हैं, सभी इस राष्ट्र के सम्मानित नागरिक हैं। इस राष्ट्र के गठन एवं समासिक संस्कृति के निर्माण में उनकी भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वे सभी अपनी निजता को समेटे हुए संपूर्ण देश में अपनी सुगंध का विस्तार कर सकें,देश में ऐसा वातावरण होना चाहिए। मगर ***धार्मिक उन्माद अथवा इस्लामिक कट्टरता व कठमुल्लापन की कतई उन्हें छूट नहीं दी जा सकती।*** देश के संविधान की मूल भावना भी यही है। हम ***भारत को एक संप्रभुतासंपन्न, समतामूलक, सर्वधर्म की आत्मा से ओत-प्रोत प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में देखना चाहते हैं, जहां सबको सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके*** और साथ ही विचार-अभिव्यक्ति व आस्था की स्वतंत्रता हो।

15.03.2002

वर्तमान आर्थिक संकट के पीछे पूंजीवादी व्यवस्था मूल रूप से जिम्मेदार

*वर्तमान उत्पादिका शक्ति या संसाधनों के एक तिहाई का ही हो रहा उपयोग

-श्यामल नंदी

हमारे देश की अर्थव्यवस्था वर्तमान दौर में संकट में है। इस संकट की मुख्य वजह पूंजीवादी व्यवस्था है जिसमें वृहद पूंजी का मूल मकसद आर्थिक संकट को जीवित रखते हुए अधिकतम मुनाफे का सृजन करना है। भारत की अर्थव्यवस्था का अगर गहराई से विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे कि कुल उत्पादिका शक्ति यानी संसाधनों का मात्र एक तिहाई का ही उपयोग हो रहा है। जबकि बाकी दो तिहाई यों ही बेकार पड़ी हुई है। अगर संसाधनों का पूरी तरह से सदुपयोग हो तो उपभोक्ता सामग्रियों की मात्रा तीन गुणा तक बढ़ायी जा सकती है। इससे हमारे देश की बड़ी संख्या में बेरोजगार श्रम शक्ति को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं की जरूरतें भी पूरी कर उनकी दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध करायी जा सकती है। इससे आम लोगों का जीवन स्तर आशातीत रूप से उच्च स्तर पर ले जाया जा सकता है।

हमारे देश में न तो प्राकृतिक संसाधनों का और न ही श्रमशक्ति का ही अभाव है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए यही दो प्रमुख कारक होते हैं। तो फिर आर्थिक समृद्धि में रुकावट कहां है? दरअसल खुशहाली के पीछे असली रुकावट है यहां की पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली जो पूंजीपति वर्ग को उत्पादन के संसाधनों पर निर्बाध नियंत्रण देती है। जिन श्रमजीवी वर्ग द्वारा उत्पादन के संसाधनों का सृजन हो रहा है वे ही इन संसाधनों पर अधिकार से वंचित हैं। जबकि बमुश्किल एक फीसदी आबादी राष्ट्रीय संपदा के 73 फीसदी पर काबिज है। आंकड़े बताते हैं कि 55 परिवारों के हाथ में जितनी संपत्ति है वह 120-125 करोड़ आबादी की संपत्ति के बराबर है। देश की 20 करोड़ आबादी रात को भूखे पेट सो जाती है जबकि 60 फीसदी आबादी या तो बेरोजगार है या अर्द्ध बेरोजगार है। उत्पादन के तमाम संसाधन जैसे कच्चा माल, भवन, उपकरण-मशीनें आदि पर श्रमजीवी वर्ग का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वह इनका उपयोग अपने लिए नहीं कर पाता जबकि यह एक कठोर सत्य है कि इन संसाधनों का सृजन श्रमिक व कर्मचारी वर्ग ने किया है।

दरअसल आम जनता की गरीबी और आर्थिक बदहाली की मुख्य वजह है कि पूंजीपति वर्ग आम जनता की जरूरतों को पूरी करने के लिए नहीं बल्कि अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए उत्पादन करता है। वह उसी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जिससे उसे अधिकतम मुनाफा सुनिश्चत हो। मान लिया जाये कि एक कारखानें की उत्पादन क्षमता एक लाख यूनिट है। बाजार की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाता है कि अगर प्रति माह कारखाने में 20,000 यूनिट , 30,000 यूनिट, 50,000 यूनिट, 75,000 यूनिट और एक लाख यूनिट सामग्री या सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उससे प्रति यूनिट मुनाफा 500/-, 480/-,420/-, 380/-, 340/- में बेचना संभव होगा। इससे मालिक का मुनाफा क्रमशः 10 लाख रु., 12 लाख, 10.50 लाख, 8.25 लाख, 5.50 लाख होंगे। इससे मालिक केवल 30,000 यूनिट वस्तु या सेवा का उत्पादन करेगा। चूंकि यह उसका अधिकतम मुनाफा है। इसका अर्थ है कि कारखाने की कुल उत्पादन क्षमता का केवल 30 फीसदी उपयोग में लाया जा रहा है। शेष 70 फीसदी क्षमता अनुपयोगी रह जा रही है। अगर मान लेते हैं कि उत्पादन सामग्री जूतों का जोड़ा है तो केवल 30 हजार लोग 480/- रुपये के मूल्य वाला जूता खरीद सकेंगे। जबकि 70 हजार लोग इन जूतों से वंचित रह गए। जबकि जूतों की आवश्यकता एक लाख से भी अधिक हो सकती है।

अब देखिये कि कारखाने में एक माह में एक लाख जूते बनाने की क्षमता है जिसका अर्थ हुआ कि प्रतिदिन 500 श्रमिक की जरूरत होगी। वहीं 30 हजार जोड़ा जूते बनाने के लिए मात्र 175 श्रमिक की जरूरत होगी। मान लिया कि कारखाने में 30 श्रमिक कार्यरत हैं तो मालिक और 200 श्रमिकों को नियुक्त कर एक लाख जोड़े जूते नहीं बनवायेगा बल्कि वह 300 वर्तमान श्रमिकों में से 125 श्रमिकों की छंटनी कर 175 श्रमिकों से ही 30 हजार जोड़े जूते बनवायेगा। वह अधिकतम मुनाफे के लिए वह 200 अतिरिक्त श्रमिकों को नियुक्त करने के बदले 125 श्रमिकों को बेरोजगार बनाना बेहतर समझेगा। इसे वर्तमान में छंटनी किए गए 125 श्रमिकों के अतिरिक्त 200 श्रमिकों को मिलाकर कुल 325 श्रमिक अपना रोजगार खो रहे हैं। ये बेरोजगार श्रमिक पहले से बेरोजगारों की फौज में इजाफा करेंगे। इसका सीधा मतलब होगा कि ये 325 बेरोजगार श्रमिकों के चलते उपभोक्ता सामग्रियों और सेवाओं का बाजार कम हो जायेगा। यह बाजार का संकट बढ़ायेगा। अर्थव्यवस्था की विकास दर घटेगी। हालांकि अगर कारखाने की अधिकतम क्षमता का उपयोग होता तो वह न सिर्फ बेरोजगारी को कम करता बल्कि उपभोक्ताओं का जीवन स्तर उन्नत करता।

एक और कारण से पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर बाजार संकुचित हो रहा है। वह है ऑटोमेशन अर्थात कारखाने के मालिक मुनाफे के एक हिस्से से अत्याधुनिक मशीनें खरीदते हैं जिससे कम श्रमिक-कर्मचारियों से ही उनकी उत्पादन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसका भी सीधा असर रोजगार के संकोचन पर पड़ता है। बेरोजगारी बढ़ती है और यह बढ़ी हुई बेरोजगारी आर्थिक मंदी को और बढ़ाती है। इसका असर यह होता है कि नये-नये कारखाने खुल नहीं पाते हैं जिससे मशीनें, निर्माण सामग्री, सीमेंट जैसी बुनियादी ढांचों की सामग्री की मांग कम होती है। इसलिए संरचनात्मक क्षेत्र (कोर सेक्टर) के कारखाने भी मंदी का शिकार होते हैं। फलस्वरूप वहां भी छंटनी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

इससे यह पता चलता है कि वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मकसद उपभोक्ताओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना नहीं है बल्कि पूंजीपति के लिए अधिकतम मुनाफा अर्जित करना है। इसलिए अगर अर्थव्यवस्था को अधिकतम लोगों की जरूरतों को पूरी करना है तो निजी स्वामित्व वाली पूंजीवादी व्यवस्था की जगह सामूहिक सवामित्व वाली अर्थव्यवस्था को लागू करना होगा। यह समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को वृहद एवं एकाधिकारवादी पूंजीपति वर्ग ने टिका रखा है। उसी के वर्गीय हितों की रक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकार राज्य व्यवस्था का इस्तेमाल करता है। चुनाव आयोग से लेकर पूरी शासन व्यवस्था इसी वर्गीय स्वार्थ की रक्षा में नियोजित है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए सामाजिक क्रान्ति की जरूरत है। वर्तमान बुर्जुआ शासन व्यवस्था के तहत होने वाली चुनाव प्रक्रिया के जरिये यह कतई संभव नहीं है। इस शासन व्यवस्था को बदलने के लिए वर्गीय चेतना से लैस जनता की संग्रामी और एक्यबद्ध शक्ति का निर्माण जरूरी है। लेकिन जब तक यह वृहद एकता कायम नहीं होती तब तक श्रमिक वर्ग की पार्टी अर्थात् विप्लवी कम्युनिष्ट पार्टी के नेतृत्व में पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण, दमन के खिलाफ अविराम संग्राम जारी रखना होगा।

वर्गीय चेतना से लैस संग्रामी जनता कभी धीरे तो कभी तेजी से जन आंदोलन को ऐसे स्तर तक ले जायेगी जब वर्गीय चेतना से लैस संग्रमी जनता के भीतर से क्रान्तिकारी विकल्प व्यवस्था कायम होगी जो पूंजीवादी शासन व्यवस्था की जगह वास्तविक जनता की शासन व्यवस्था क्रान्ति के जरिए समाजवादी व्यवस्था कायम करने में सफल होगी।

■ अनुवादः मनोरंजन पाण्डेय

युद्धोन्माद, कारपोरेट और वैश्विक अर्थव्यवस्था

शैलेन्द्र चौहान

यह जो वैश्विक अर्थतंत्र है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जिसके शीर्ष पर काबिज हैं, उसकी निरंतरता और उसका फलते-फूलते रहना मुख्यतः दो तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला- आपूर्ति व मांग में संतुलन और दूसरा- श्रमिक/कर्मचारी वर्ग के समर्थन का बना रहना।

पहले मोर्चे पर कंपनियां संकट में हैं। पूंजी की अकूत उपलब्धता और तकनीक के विकास ने उत्पादन में जिस वृद्धि दर को रेखांकित किया है उस अनुपात में मांग नहीं बढ़ पा रही है। यह बड़ा संकट है जिससे पार पाने को कंपनियां तमाम ज़द्दोज़हद में लगी हैं।

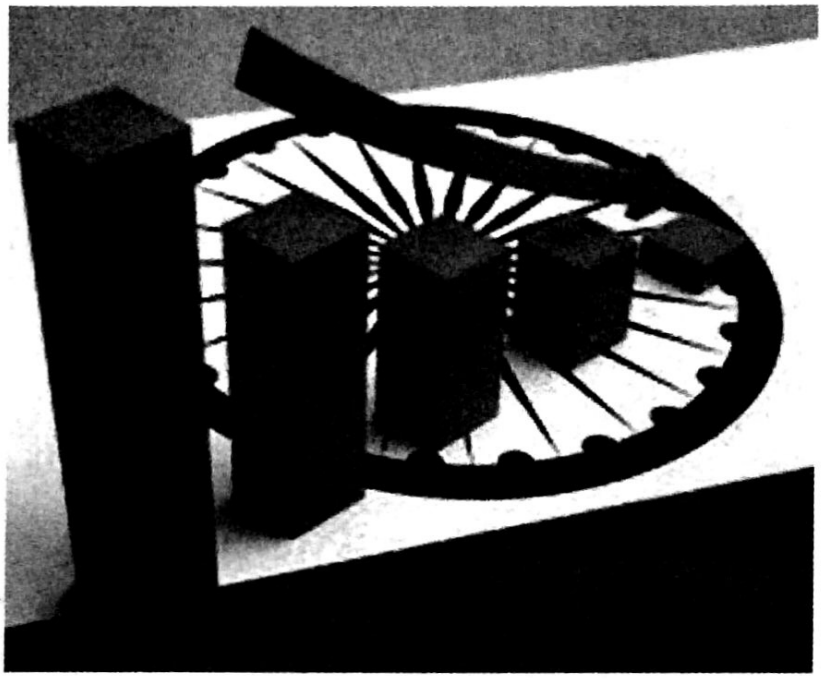

मुश्किल यह है कि उत्पादन और मांग में बढ़ते असंतुलन का संकट नवउदारवाद की उसी आर्थिक सैद्धांतिकी से उपजा है जिसने इन कंपनियों को तो आर्थिक रूप से अतिसमृद्ध किया है किंतु आम लोगों, जो खरीदार हैं, की आमदनी की वृद्धि दर को सीमित किया है।

हम अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स से रूबरू होते रहते हैं कि किस तरह आमदनी का असंतुलन बढ़ता जा रहा है और विकास दर के अधिकतम लाभ दो-चार प्रतिशत अमीर लोगों के हिस्से में जा रहे हैं।

तो-उत्पादन के स्रोतों के मालिकान की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और इस पूंजी का विनियोग वे उत्पादन बढ़ाने में करते जा रहे हैं, लेकिन-जो खरीदारों का विशाल वर्ग है, उसकी क्रय शक्ति में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही है।

नतीजा में- बाजार उत्पादित माल से अटे पड़े हैं लेकिन खरीदारों का अभाव है। यह संकट वैश्विक है, किन्तु भारत में इसके नकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक हैं क्योंकि- आमदनी के संकेन्द्रण और बढ़ती आर्थिक विषमता की रफ्तार पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में ही है।

अभी कुछ महीने पहले, जब दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक बाजार ने 'पूजा उत्सव' मनाया था तो कंपनियों को खासी निराशा हाथ लगी थी। आमतौर पर भारतीय इन पूजा उत्सवों में ही उपभोक्ता सामग्रियों की खरीदारी सबसे अधिक करते हैं। इन अवसरों पर लालच बढ़ाने के लिये बाजार 'ऑफर्स' की बरसात करता है। किन्तु-जैसा कि बाजार के खिलाड़ियों ने निराशा में बताया-'' पूरे पूजा उत्सव में बिक्री उम्मीद से 40 प्रतिशत कम रही।''

कंपनियों के लिये यह बड़ा झटका था। गोदामों में माल पड़े रह गए। लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि तमाम ऑफर्स का लाभ उठा कर वे अपना घर नई तकनीकों से लैस उपभोक्ता सामग्रियों से भर पाते। ऐसी स्थितियां पिछले कई वर्षों से घनीभूत होती गई हैं और इसके यथासंभव निदान के लिये कंपनियां नित नई चालें चलती रही हैं।

अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे मुक्त होती जाती है, बाजार की शक्तियां उसी अनुपात में सत्ता-संरचना में प्रभावी होती जाती हैं। नीतियों का रुख आमलोगों से अधिक कंपनियों के हितों के अनुरूप मुड़ता जाता है।

तो-उत्पादन और मांग का बढ़ता असंतुलन झेल रहे भारतीय बाजार ने ऐसी आर्थिक नीतियों पर जोर दिया जिसमें 'लिक्विडिटी' यानी कि 'तरलता'-यानी कि 'कैश फ्लो' को बढ़ाया जाए। भारत सरकार और रिजर्व बैंक में बढ़ते तकरार का यह एक बड़ा कारण रहा है।

लिक्विडिटी' को बढ़ाने के लिये जरूरी था कि बचत को हतोत्साहित किया जाए और खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। आमतौर पर भारतीय बचत प्रेमी होते हैं। अपनी जरूरतों को काट-छांट कर भविष्य के किसी गाढ़े वक्त के लिये बचत करना पीढ़ियों से उनके संस्कार में शामिल रहा है।

बाजार प्रेरित नीति-निर्माताओं ने बचत को हतोत्साहित करने के हर संभव उपाय करने शुरू किए। 'फिक्स डिपॉजिट' भारतीयों का एक प्रिय रास्ता रहा है बचत के लिये। ब्याज दर घटा कर और परिपक्वता पर टैक्स लगा कर इसे इतना हतोत्साहित किया गया कि आज बचत का यह तरीका सबसे निचले पायदान पर चला गया। इसके बदले 'म्युचुअल फंड' का विज्ञापन जोर-शोर से किया जाने लगा जिसमें आमलोगों का पैसा सीधे बाजार की पूंजी बन जाता है और लाभ के साथ ही रिस्क में भी लोग हिस्सेदारी निभाते हैं।

विज्ञापन उपभोक्तावाद का प्रमुख हथियार है जो लोगों की आकांक्षाओं को उनकी हैसियत की सीमाओं के पार जाने को विवश कर देता है। बैंकों द्वारा आसान शर्त्तों पर उपभोक्ता ऋण उन्हें कर्जदार बनाता जाता है और अपने घरों को अपनी हैसियत से भी अधिक उपभोक्ता सामग्रियों से भरने में लोग मध्यवर्गीय गर्व का अनुभव करते हैं। ''पांव उतना ही पसारिये जितनी लंबी आपकी चादर है''- यह कहावत सदियों से भारतीय लोक